काशी विश्वनाथ कोरिडोर पर भारी पड़ रहा है लोगों की जिंदगी का सवाल

प्रत्यक्ष मिश्रा

यूपी विधानसभा चुनाव-2022 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वनाथ मंदिर का ख्याल आना स्वाभाविक है।

वायदों के दौर को पहले ही शासनकाल के दौरान देख चुके हैं। आर्थिक मोर्चे पर त्राहिमाम कर रही अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के बाद महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण के गहरे घाव धोने के लिए जनता को अब 900 करोड़ लागत से 5 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण वाली काशी विश्वनाथ गलियारे की सौगात दी जा रही है। लेकिन भाजपा की यह तरकीब काम करती नहीं दिख रही है। लोगों की जिंदगी के सवाल बीजेपी के मंसूबों पर भारी पड़ रहे हैं।

किसान आन्दोलन से जागा, सिरमौर

भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में? किसान आंदोलन प्रमुख है। सरकार को दूर-दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि तीन विधेयक, जो संसद में बिना किसी बहस, विचार के पारित कर दिए गए हैं उनसे एक दिन ऐसा भी आन्दोलन खड़ा हो सकता है जिसके कारण सरकार की कुर्सी पर आन गुजरेगी।

पश्चिमी यूपी, किसानों की मां है। पूर्वोत्तर को देखते हुए, पश्चिम यूपी में भाजपा के वर्चस्व में भारी गिरावट आई है। किसान आन्दोलन की भूमिका इसमें, अहम रही है। भाजपा भी पश्चिमोत्तर में अपने वोट बैंक को भली-भांति समझ रही है, 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की स्थिति खस्ताहाल ही रही थी। कुछ मंडल ऐसे थे जहां, भाजपा का केवल खाता ही खुल पाया था। वहीं किसान आन्दोलन में क़रीब 735 किसानों की मौत हुई थी, अब देखना होगा कि पश्चिमोत्तर, किसान आन्दोलन की बुनियाद पर खड़े सिरमौर को किस तरफ लेकर जाता है।

निजीकरण के तीखे स्वर

पिछले कुछ वर्षों में निजीकरण के प्रति केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण एक प्रकार का रहस्योद्घाटन ही रहा है। तमाम एयरलाइंस बेचने के बाद, मोदी सरकार की निगाहें सरकारी बैंकों पर आ टिकी हैं। सरकार अब बैंकों पर दांव खेलने की तैयारी में है।

बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बैंककर्मियों की हड़ताल जारी है। बैंक कर्मचारियों के 9 यूनियनों ने मिलकर इस हड़ताल का आह्वान किया है। देश भर के सभी सरकारी बैंकों के 9 लाख से अधिक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। पहले दिन के हड़ताल से करीब 19 हजार करोड़ के बैंकिंग कामकाज के प्रभावित होने का अनुमान है।यदि बैंकों को भी निजीकरण के दंभ में धकेल दिया गया तो भारी बेरोजगारी के बीच 9 लाख कर्मचारियों को ऐतिहासिक धक्का लगेगा।

महा बेरोजगारी की इंतहा

अगर बात देश की राजधानी दिल्ली

की करें तो सितंबर में दिल्ली में बेरोजगारी की दर 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर करीब 17 फ़ीसदी हो गई थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी या सीएमआईई के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। देश के उत्तरी राज्यों में बढ़ती बेरोजगारी की बात करें तो राजस्थान में बेरोजगारी की दर 18 फ़ीसदी के करीब पहुंच गई है, जबकि हरियाणा में यह 20.3 फ़ीसदी, जम्मू कश्मीर में 21.6 फ़ीसदी पर पहुंच गयी है। बिहार, त्रिपुरा, झारखंड और पुडुचेरी में बेरोजगारी की दर 10 से 15 फ़ीसदी के बीच है। देश के उत्तरी राज्य में बेरोजगारी की दर का यह ट्रेंड मिलाजुला है।

यूपी में टीईटी का सवाल हो या फिर दरोगा भर्ती का, कोई ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें धांधली न हुई हो। बिना कोर्ट का मुंह देखे, कोई भर्ती नहीं होती।

वहीं निजीकरण की बाट जोह रहे रेल मंत्रालय ने तो हद ही कर दी। ग्रुप-डी, एनटीपीसी के भर्ती विज्ञापन को करीब 3 साल होने जा रहे हैं, रेल मंत्रालय को छात्रों और शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर-करके जगाया तो पता चला कि हां हमने कभी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन भी निकाला था। खैर अब मंत्रालय ने आंख मूंदते हुए परीक्षा तारीख़ तो घोषित कर दी है।

कमर तोड़ती महंगाई

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर तीन महीने के उच्च स्तर 4.91 प्रतिशत हो गई, जिसमें खाद्य कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई, केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 1.87 प्रतिशत हो गई, जो अक्टूबर महीने में 0.85 प्रतिशत थी।

नवंबर में ईंधन और हल्की मुद्रास्फीति एक महीने पहले 14.4 प्रतिशत के मुकाबले 13.4 प्रतिशत रही, जबकि सब्जियों की मुद्रास्फीति एक महीने पहले -19.4 प्रतिशत के मुकाबले -13.6 प्रतिशत दर्ज की गई। नवंबर में कपड़ा और फुटवियर मुद्रास्फीति एक महीने पहले 7.5 प्रतिशत की तुलना में 7.9 प्रतिशत थी, जबकि परिवहन और संचार मुद्रास्फीति अक्टूबर में 10.9 प्रतिशत के मुकाबले 10.02 प्रतिशत थी।

वायदों का दौर खत्म हो चुका है। अब सवालों का दौर है, सवाल है कि क्या ऑक्सीजन के अभाव में मौत की शैय्या पर लौटने वाले नागरिकों के परिजन, भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से अपने स्वजनों के इस दंभ को भुला पाएंगे?

अब देखना होगा कि यूपी की जनता ऐतिहासिक किसान आन्दोलन के बाद महाबेरोजगारी से जूझ रहे उत्तम प्रदेश की राह पर उतर प्रदेश की कमान किसे सौंपती है?

भारत में आत्महत्याओं के आँकड़ों ने की पुरानी हदें पार

जनचौक ब्यूरो

'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो' द्वारा साल 2020 के लिए जारी नई रिपोर्ट में भारत में आत्महत्या के संबंध में जो तथ्य सामने आए हैं, वे आजकल अख़बारों, टी.वी. चैनलों, पत्रिकाओं, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोरोना के नाम पर भारत सरकार द्वारा पहले थोपे गए लॉकडाउन और फिर तरह-तरह की आंशिक पाबंदियों को जब पूरे देश में मूक और सरगर्म समर्थन मिल रहा था तब ही 'मुक्ति संग्राम' में प्रकाशित कई लेखों में यह आशंका जताई गई थी कि इन नीतियों के आम लोगों के लिए भयंकर परिणाम निकलेंगे। न सिर्फ़ आर्थिक तौर पर ही महँगाई, बेरोज़गारी, भुखमरी के रूप में ही लोगों ने इन नीतियों को अपने पर झेला, बल्कि इन नीतियों से लोगों की मानसिक हालत पर भी बहुत बुरे असर देखने को मिल रहे हैं। 'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो' की ताज़ा रिपोर्ट की रोशनी में यह उजाले की तरह साफ़ है कि कोरोना काल में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का मूल्य लोगों के विशाल समूह ने अपने ख़ून से उतारा है और उतार रही है। रिपोर्ट में आत्महत्याओं संबंधी दिए गए तथ्यों पर बातचीत करने से पहले यह बात करनी ज़रूरी है कि कोरोना काल में अपनाई गई नीतियों के कारण बेशक आत्महत्याओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई, परंतु इन आत्महत्याओं की जड़ सिर्फ़ कोरोना काल की नीतियों में ही नहीं बल्कि निजी मिललकियत पर टिके इस समूचे पूँजीवादी ढाँचे में तलाशने की ज़रूरत है

'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो' की रिपोर्ट में आत्महत्याएँ करने वालों को 9 वर्गों में बाँटा गया है, दिहाड़ीदार मज़दूर, कृषि-क्षेत्र में लगे लोग, पेशेवर/ तनख़्वाहदार मुलाजिम, विद्यार्थी, स्वरोज़गार प्राप्त लोग, घरेलू कामकाज सँभालने वाली औरतें, सेवा मुक्त लोग आदि। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 के मुक़ाबले 2020 में कुल आत्महत्याओं में 10त्न बढ़ोतरी हुई और इससे 2020 में आत्महत्याओं का कुल आँकड़ा 1,53,052 बनता है। भारत में एक साल के अंतराल में किसी भी और साल के मुक़ाबले अधिक आत्महत्याएँ हुई हैं। इससे आत्महत्याओं की दर में भी तेज़ बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2019 में जहाँ यह दर प्रति लाख जनसंख्या पर 10.4 आत्महत्याएँ थीं, वहाँ 2020 में 11.3 प्रति लाख हो गई है। सबसे अधिक तेज़ी से विद्यार्थियों में ख़ुदख़ुशियाँ बढ़ी हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई ख़ुदख़ुशियों में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 21.20त्न की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, कुल आत्महत्याओं में दिहाड़ी मज़दूरों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 2020 में 37,666 दिहाड़ी मज़दूरों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्याओं का 24.6 है। याद रहे कि 2014 में कुल आत्महत्याओं में दिहाड़ी मज़दूरों की हिस्सेदारी 12त्न थी, जो कि मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल के दौरान 24त्न से अधिक हो गई है। यह आँकड़ा वास्तव में मज़दूरों के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। आम तौर पर मोदी सरकार की नीतियाँ और कोरोना काल में अपनाई गई नीतियों के कष्ट सबसे अधिक मज़दूरों को ही झेलने पड़े हैं और पड़ रहे हैं।

पिछले साल जब कोरोना की वजह से सभी काम बंद थे, मज़दूर भूखे रहने पर मजबूर थे, प्रवासी मज़दूर दोपहर की धूप और भूख से सड़कों पर तड़प रहे थे, तो मोदी और राज्य सरकारें ए.सी. कमरों में बैठकर उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह दे रही थीं तो दूसरी तरफ़ मज़दूर विरोधी क़ानूनों का मसौदा तैयार किया जा रहा था। पूँजीवादी व्यवस्था के कार्यों और सरकारों के रवैये को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले साल देश में 37,000 से अधिक दिहाड़ी मज़दूरों ने आत्महत्या की।

दिहाड़ीदार मज़दूरों को छोड़कर कुल आत्महत्याओं का सबसे बड़ा हिस्सा घरेलू औरतों (14.6 प्रतिशत), स्वरोज़गार प्राप्त लोगों (11.3 प्रतिशत) और बेरोज़गारों (10.2 प्रतिशत) का बनता है। खेतीबाड़ी में लगे लोगों में से पिछले साल 10,677 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 5579 किसान थे और 5098 खेत मज़दूर थे। यदि इन खेतिहर मज़दूरों की संख्या को दिहाड़ीदारों की संख्या में जोड़ दिया जाए, तो मज़दूरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की संख्या कुल आत्महत्याओं के एक चौथाई से अधिक हो जाएगी। जहाँ कोरोना काल में अंबानी और अडानी जैसे मुट्ठी-भर पूँजीपतियों की दौलत बड़े पैमाने पर बढ़ी, वहीं कई छोटे कारोबार नष्ट हो गए और 2020 में बिगड़ती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण 11,000 से अधिक व्यापार और कारोबार वालों ने आत्महत्या कर ली। इस श्रेणी में आत्महत्याओं में सबसे तेज़ वृद्धि व्यापारियों में देखी गई है। 2019 की तुलना में 2020 में व्यापारियों द्वारा आत्महत्या में 50त्न से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कोरोना काल से पहले भी छोटे व्यवसाय और मध्यम वर्ग की हालत लगातार पतली होती जा रही थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान पिछले कई दशकों में पहले कभी न देखी गई गति से छोटे कारोबार ख़त्म हुए और खाते-पीते मध्यम वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती गई।

आत्महत्याएँ करने वालों में बड़ा हिस्सा 18-45 आयु वर्ग के लोगों का बनता है और 2020 में इस आयु वर्ग के कुल 1,00,716 लोगों ने आत्महत्या की। यह वर्ष 2020 के कुल आँकड़े का 65 प्रतिशत से अधिक है। यह दुखद है कि किसी भी उम्र के लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक आत्महत्याएँ समाज के सबसे ऊर्जावान और उत्पादक तबके में होती है और यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मौजूदा व्यवस्थान सिर्फ़ मानवीय मूल्यों पर खरा नहीं उतरता है, बल्कि अपने स्वयं के मानकों (सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, आदि) से भी दूर है।

'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' की रिपोर्ट में भी आत्महत्या के विभिन्न कारणों को समझने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट लगभग 15 अलग-अलग कारणों की पहचान करती है, जिनके कारण अलग-अलग मामलों में आत्महत्याएँ हुई हैं। पहचाने गए कुछ कारणों में पारिवारिक समस्याएँ, बीमारी, नशा/शराब, क़र्ज़, बेरोज़गारी, ग़रीबी, व्यवसाय की समस्याएँ, संपत्ति विवाद, सामाजिक स्थिति की हानि आदि शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से पारिवारिक समस्याओं में सबसे अधिक आत्महत्याएँ हुई, जो सभी आत्महत्याओं का 33.6 प्रतिशत है। बीमारी (18 प्रतिशत) और नशा (6 प्रतिशत) आत्महत्या के अगले प्रमुख कारण हैं।

जब आत्महत्या की बात आती है, तो कुछ लोग इसे किसी व्यक्ति की दिमाग़ी जैविक संरचना के नतीजे के तौर पेश करने लगते हैं, लेकिन जैविक रूप से, मानव मस्तिष्क की संरचना में लंबे समय से (कम-से-कम कई हज़ार साल) कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आत्महत्याओं में तेज़ी से वृद्धि दुनिया में पूँजीवादी व्यवस्था के विस्तार से जुड़ी एक हालिया घटना है। इसलिए आत्महत्या की यह व्याख्या ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ लोग इस घटना को आधुनिकता के प्रसार से जोड़ते हैं, लेकिन यह इस घटना की सटीक व्याख्या नहीं है। क्योंकि समाजवादी रूस (रूस 1956 तक एक समाजवादी देश था) कई पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक आधुनिक हो गया था। इसके बावजूद यहाँ आत्महत्याएँ नाममात्र ही हुई, जबकि पश्चिमी यूरोप और कई पिछड़े पूँजीवादी देशों में यह संख्या बहुत अधिक थी। आत्महत्याओं के संबंध में एक और मत यह है कि आत्महत्या का कारण शुद्ध रूप से आर्थिक है और इस व्यवस्था में असमानता, ग़रीबी, बेरोज़गारी, बढ़ता क़र्ज़ लोगों को आत्महत्या की ओर धकेलता है। बेशक यह व्याख्या इस मायने में सही है कि यह मौजूदा बाहरी परिस्थितियों से इस घटना की व्याख्या करती है, लेकिन यह भी इस घटना की सटीक व्याख्या नहीं करती। वास्तव में, आत्महत्याओं का मूल कारण संपूर्ण पूँजीवादी ढाँचा है, जिसमें आर्थिक प्रबंधन (सामाजिक उत्पादन और निजी संपत्ति पर आधारित) और उस पर बने सामाजिक संबंधों का कुल जोड़ होता है। इस प्रणाली में लाजिमी ही आर्थिक कठिनाइयों के अलावा, राजनीतिक और सामाजिक उत्पीड़न सबसे अधिक विशाल मेहनतकश जनता का होता है और कुल आत्महत्याएँ आबादी के इस हिस्से में अधिक होती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यम वर्ग, अन्य उच्च वर्गों के लोग आत्महत्या नहीं करते। भारत की आत्महत्या की राजधानी के रूप में जाने जाने वाले कोटा में आमतौर पर मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के छात्र आते हैं और हर साल कई छात्र वहाँ आत्महत्या करते हैं। पूँजीवादी संबंधों में बेगानापन (मनुष्य की श्रम से बेगानगी, मनुष्य की प्रकृति से बेगानगी, मनुष्य की ख़ुद से बेगानगी और मनुष्य की मनुष्य से बेगानगी) ही मानसिक बीमारी और आत्महत्या की जड़ है।

यह सच है कि हाल के दिनों में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आत्महत्याएँ बढ़ी हैं, लेकिन इसका समाधान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही नहीं, बल्कि पूरे पूँजीवादी समाज को बदलना भी है। लाजिमी तौर पर, भाजपा सरकार ऐसी नीतियाँ लागू कर रही है जिनके कारण हाल के दिनों में आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सत्तारूढ़ आरएसएस-बीजेपी जो कर रही है, वो है मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था का बचाव, ऐसी व्यवस्था जो आत्महत्याओं और अन्य मानसिक समस्याओं की उपजाऊ जन्मभूमि है। इस समस्या का पुख़्ता हल पूँजीवादी ढाँचे की तबाही से ही शुरू करके संभव है। **-नवजोत, पटियाला**